आंध्र और शराबबंदी

रजि० नं० बी ४४४८
लाअिसेन्स नं० १५

हरिजनसेवक

दो आना

(संस्थापक : महात्मा गांधी)

भाग १७ सम्पादक : मगनभाअी प्रभुदास देसाअी अंक १०

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाअी देसाअी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद–९

अहमदाबाद, शनिवार, ता० ९ मअी, १९५३

वार्षिक मूल्य देशमें रु० ६
विदेशमें रु० ८; शि० १४

हमारा अनोखा मिशन

[चांडिल सर्वोदय-सम्मेलनमें ता० ७–३–'५३ को दिये गये विनोबाजीके पहले दिनके भाषणकी दूसरी किस्त।]

२

हमारा असली काम और अुसकी दृष्टि

मैं दूसरी मिसाल दूं। अभी खादी-बोर्ड बन रहा है। सरकार खादीको मदद देना चाहती है। पंडित नेहरूने कहा, 'मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जो काम चार साल पहले हो हो जाना चाहिये था, वह अितनी देरीसे क्यों हो रहा है?' वे महान हैं। अुनका दिल महान है। वे आत्मनिरीक्षण करते हैं और अिस तरहका भाषा बोलते हैं। अब हमारा काम है, चरखा-संघका काम है कि सरकार खादीको बढ़ावा देना चाहती है, खादीका अुत्पादन बढ़ाना चाहती है, तो अुसको कुछ मदद दें; क्योंकि चरखा-संघको अिस कामका अनुभव है और अनुभवियोंकी मदद अैसे कामके लिअे जरूरी है। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूं कि अेक नागरिकके नाते और अेक माहिरके नाते अपनी सरकारको जो मदद देना जरूरी है, वह देना चाहिये। लेकिन अगर हम अुसमें खतम हो जायं, समाप्त हो जायं, तो हमने खादीकी वह सेवा नहीं की, जैसी कि हमसे अपेक्षा है। हमें तो खादीके बारेमें अपनी दृष्टि स्पष्ट और शुद्ध रखनी चाहिये और अुस दिशामें काम करते हुअे सरकारको खादी-अुत्पादनमें जो मदद पहुंचानी चाहिये, वह पहुंचाना चाहिये। हमें युद्ध मिटानेके तरीके ढूंढ़ने चाहिये। और तिस पर भी युद्ध चलें, और हमें जरूरी सिपाहियोंको मददमें जाना पड़े तो जाना चाहिये। यह तो युद्धका हिस्सा ही है, अैसा कह कर अुसका अिनकार करेंगे अैसी बात नहीं, पर ध्यानमें रखेंगे कि वह हमारा असली काम नहीं है। हमारा खादी-काम ग्राम-राज्यकी स्थापनाके लिअे हो सकता है।

खादी-काममें सरकारी सहयोगकी मर्यादा

अिस मर्तबा पंडित नेहरू मिलने आये और बड़े प्रेमसे बोले। मैंने नम्रतासे अुनका बहुत कुछ सुन लिया। और फिर जब अुन्होंने कुछ सलाह-मशविरा करना चाहा, तो मैंने अपने विचार थोड़ेमें प्रकट कर दिये। मैंने कहा कि खादीके लिअे और ग्रामोद्योगके लिअे भी सरकारकी तरफसे अगर मैं कोअी चीज चाहता हूं, तो मैं कहूंगा कि जैसे हरअेक नागरिकको पढ़ना-लिखना आना ही चाहिये, क्योंकि नागरिकत्वका वह अंश है, अनिवार्य अंश है, अैसा हम मानते हैं और अिसलिअे हमारी सरकार सबको शिक्षित बनानेकी, पढ़ना-लिखना सिखानेकी जिम्मेवारी महससू करती है, मान्य करती है। चाहे अुस पर वह पूरा अमल न करने पाये; परिस्थितिके कारण आंशिक अमल करे, लेकिन जब तक अुसका पूरा अमल नहीं हुआ है, सारेके सारे लोग पढ़ना-लिखना नहीं जान गये हैं, तब तक हमने अपना पूरा काम नहीं किया, अिस तरहका खटका दिलमें बना रहेगा। वैसे ही हमारी सरकार यह माने, यह विचार कबूल करे कि हिन्दुस्तानके हरअेक ग्रामाणको, हरअेक नागरिकको सूत कातना सिखाना चाहिये। जो ग्रामाण, जो नागरिक सूत कातना नहीं जानते, वे अशिक्षित हैं, अितना माने और बाकीका सब काम जनता करे। हम सरकारसे पैसेकी मदद नहीं मांगें, परन्तु यह विचार अगर वह स्वीकार करती है, तो अुससे हमें अधिकसे अधिक मदद मिलती है। तो यह सब अुन्होंने सुन लिया। मैं समझता हूं कि अुनके हृदयको तो वह जंचा ही होगा, पर सहज विनोदमें अुन्होंने पूछा कि सूत कातना अगर सबको सिखा दें, तो अुसके अुपयोगका सवाल आयगा। तो मैंने जवाब दिया कि पढ़ना-लिखना सिखाने पर भी तो अुसके अुपयोगका सवाल रहता ही है। मैंने अैसे कअी पढ़-लिखे भाअी देखे हैं, जो थोड़ासा दो-चार साल पढ़े और अुसका अुनकी जिन्दगीमें कभी कोअी अुपयोग नहीं हुआ। अुनके लिअे काला अक्षर भैंस बराबर होता है। 'योग' के साथ 'क्षम' लगा है। यह चिंता करनी पड़ती है। पर आप देखेंगे कि मैंने खादीके लिअे सिर्फ अितनी ही मांग की है। जबकि जनताकी सरकार है और जनताकी तरफसे यह मांग होगी, तो सरकारको अुतना करना चाहिये। परन्तु अिससे अधिक लोगों पर खादी लादनेकी बात अगर कानूनसे होगी, यानी मैं अैसी मांग करूं, तो मैं कहूंगा कि मैंने अपना काम समझा नहीं है। दंड-शक्तिसे भिन्न हमें लोकशक्ति निर्माण करनी है, यह सूत्र मैं भूल गया हूं।

दंड-निरपेक्षताका निर्माण

ये दो मिसालें सहज दीं, अेक खादीकी और दूसरी भूमिदानकी। हम भूमिका मसला हल करने जायंगे तो हमारा अेक तरीका होगा। और लोकशाही सरकार अगर वह हल करना चाहेगी, और दंड-शक्तिका अुपयोग करके अुसे करना चाहेगी और करेगी, तो अुसको कोअी दोष नहीं देगा। लेकिन अुसका दूसरा मार्ग है। सरकारकी अिस तरहकी मददसे जनशक्ति निर्माण नहीं होगी, लक्ष्मी भले ही निर्माण हो। हमारा अुद्देश्य सिर्फ लक्ष्मी निर्माण करना नहीं, बल्कि जनशक्ति निर्माण करना होगा। यह सारी दृष्टि हमारे कामके पीछे है। अब यह दृष्टि हमारी स्थिर हो जाय, तो फिर हमारी कार्यपद्धति क्या होगी, अिसका विशेष वर्णन करनेकी आवश्यकता नहीं रहेगी। हर कोअी सोचेगा कि हरअेक रचनात्मक काम करनेमें हमारी अेक विशेष पद्धति होगी। अिस पद्धतिसे काम करनेसे आखिर यही परिणाम अपेक्षित होगा कि लोगोंमें दंड-निरपेक्षता निर्माण हो।

www.vinoba.in

कार्य-पद्धतिके दो अंश

अिस दृष्टिसे यदि सोचेंगे तो सहज ही ध्यानमें आयेगा कि हमारी कार्य-पद्धतिके दो अंश होंगे। अेक अंश होगा विचार-शासन और दूसरा अंश होगा कर्तृत्व-विभाजन। मुझे जरा शास्त्रीय शब्द बनानेकी आदत है, और क्योंकि संस्कृत भाषा ही मैं विशेष जानता हूं, अिसलिअे संस्कृत शब्द आ जाते हैं। तो आप जरा मुझे क्षमा करेंगे।

सर्वोदय-समाजकी आधार-शिला

विचार-शासन यानी विचार समझाना और विचार समझना, बिना विचार समझे किसी बातको कबूल न करना, बिना विचार समझे अगर कोअी हमारी बात कबूल करता है तो दुःखी होना, अपनी अिच्छा दूसरों पर न लादना, बल्कि केवल विचार समझा करके ही सन्तुष्ट रहना। हमारा सर्वोदय-समाजको योजनामें हमने जो रचना का है, अुसको कुछ लोग "लूज़ ऑर्गनाअिज़ेशन" यानी "शिथिल रचना" कहते हैं। रचनाको अगर हम शिथिल करें, तो कोअी काम नहीं बनेगा। अिस वास्ते रचना शिथिल नहीं होनी चाहिये। पर यह 'शिथिल रचना' न होते हुअे 'अरचना' है, यानी केवल विचारके आधार पर हम खड़ रहना चाहते हैं। हम किसीको आदेश नहीं देते, जिसे वे बिना समझ-बूझ ही अमलमें लायें। हम किसीका आदेश कबूल नहीं करते, जिसका कि बिना सोचे और बिना पसन्द किये हम अमल करते जायं। बल्कि हम तो सलाह-मशवेरा करते हैं। कुरानमें भक्तोंका लक्षण गाया गया है कि अुनका वह 'अम्र' यानी काम परस्परके सलाह-मशवेरेसे होता है। तो हम मशविरा करेंगे और बहुत खुश होंगे कि हमारा चीज हमारे सुननवालेने, जब कि अुसको पसन्द नहीं आया था, मान्य नहीं का और अुस पर अमल नहीं किया। अुसके अमल न करनेसे हमें बहुत खुशी होगी। और बिना समझे-बूझे अगर अमल करता है, तो हमें बहुत दुःख होगा। यह जो रचना है अुसमें मैं जितना ताकत देखता हूं, अुतना और किसी कुशल रचनामें, स्पष्ट रचनामें और अनुशासनबद्ध रचनामें नहीं देखता। अनुशासनबद्ध दण्ड-युक्त रचनामें शक्ति नहीं होती सो बात नहीं। पर वह शक्ति नहीं होता, जो शिव शक्ति है और जो हमें पैदा करना है। वह शक्ति दूसरी शक्ति है। हमारे खयालसे वह शक्ति नहीं है, अिसलिअे विचार-शासनको हम मानना चाहते हैं। अगर यह ध्यानमें आयेगा, तो विचारका निरंतर प्रचार करना हमारा अेक कार्यक्रम बनेगा, जो हम नहीं कर रहे हैं और जो हमें करना चाहिये।

विचार, विचार और विचार

जब मैं अिस दृष्टिसे सोचता हूं, तो बुद्ध भगवान्‌ने भिक्षु-संघ क्यों बनाये होंगे और शंकराचार्यने यति-संघ क्यों बनाये होंगे, अिसका रहस्य खुल जाता है। तिस पर भी अुन संघोंके जो अनुभव आये हैं, अुनके गुण-दोषोंकी तुलना करके मैंने अपने मनमें यह निर्णय किया है कि हम अैसे संघ नहीं बनायेंगे, क्योंकि अुनके गुणोंसे अुनके दोष अधिक होते हैं। यह अनुभव आया है, अिसलिअे हम संघ तो नहीं बनायेंगे, पर अुनको क्यों बनाने पड़े, अिसका खयाल अुससे आ जाता है। निरंतर, अखंड बहते हुअे झरनेकी तरह सतत घूमनेवाले और लोगोंके पास सतत विचार पहुंचानेवाले लोग होने चाहियें। अुसके बगैर सर्वोदय-समाज काम नहीं कर पायेगा। लोगोंके पास पहुंचनेके जितने मौके मिलें, अुतने प्राप्त करने चाहियें। लोग अेक बार कहने पर नहीं सुनते हैं, तो दुबारा कहनेका मौका आने पर हमें खुशी होनी चाहिये। अितना विचार-प्रचारका अुत्साह और अितनी विचार पर श्रद्धा, विचार-निष्ठा हममें होनी चाहिये। लेकिन हमारी हालत यह है कि हममें से बहुतसे लोग भिन्न-भिन्न संस्थाओंमें गिरफ्तार हो गये हैं। अिसका थोड़ा जिक्र बादमें करूंगा, सिर्फ अभी अुल्लेख मात्र किया है। यद्यपि वे संस्थायें महत्त्वकी हैं, तो भी हमें संस्थाओंकी आसक्ति न हो, भक्ति रहे और अुनका काम जारी रखें। लेकिन संस्थामें कुछ मनुष्य अैसे हों, जो सदा घूमते रहें। अिस तरहकी रचना और अैसा कार्यक्रम हम नहीं करेंगे, तो हमारा विचार क्षीण होगा और विचार-शासन नहीं चलेगा।

पत्रकसे पत्रक ही पैदा होते हैं

बिहारके लोग कुछ अभिमानसे कहते हैं और अुन्हें अभिमान करनेका हक भी है कि भूदान-यज्ञका काम बिहारकी कांग्रेसने प्रथम अुठाया और अुसके बाद हैदराबादमें अ० भा० कांग्रेसने अुसको स्वीकार किया। तो होता क्या है? अूपरसे अेक 'सरक्यूलर' (पत्रक) आता है—"भूदानमें मदद देना कांग्रेसवालोंका कर्तव्य है।" गंगा हिमालयसे गिरती है और हरिद्वार आती है। तो वहांका पत्रक प्रांतिक समितिमें आता है। और हिमालयसे गंगा हरिद्वार आने पर आगे बहती है और गढ़मुक्तेश्वर जाती है। यह पत्रक भी प्रांतिक समितिसे जिला ऑफिसमें जाता है। गंगा कहांसे कहां भी जाय, पर वह पानी ही रहती है, गंगा ही रहती है। अुसी तरह पत्रकमें से पत्रक ही पैदा होते हैं। मैंने विनोदके तौर पर अेक दफा कहा था कि हरअेक जाति अपनी ही जातिको पैदा करती है। वैसे ही पत्रक भी पत्रक ही पैदा कर सकता है। आखिर काम कौन करेगा? काम तो करना होगा ग्रामके लोगोंको, लेकिन ग्रामके लोगों तक वह पहुंचता कहां है? वह तो अेक ऑफिससे दूसरी ऑफिसमें जाता है, वहांसे तीसरी ऑफिसमें जाता है, सिर्फ अितना ही होता है। यह जो भूदान-यज्ञका हमारा कार्यक्रम है, वह तब तक नहीं हो सकता, जब तक कि हम घर-घर नहीं पहुंचेंगे। पांच लाख देहातसे पच्चीस लाख अेकड़ जमीन हम हासिल करना चाहते हैं। यों तो आसान काम दीखता है। फी गांव पांच अेकड़ कोअी बड़ी बात नहीं। लेकिन अुतने गांवों तक पहुंचे कौन? अिसलिअे हमारे पास मुख्य साधन विचार-प्रचारका ही हो सकता है। अुसकी योजना हमें करनी चाहिये, यह हमारा कार्यक्रम होगा।

हमारा अेक औजार विचार-शासन

अगर अैसा करनेकी हमारी हिम्मत नहीं होती है, अितने गांवोंमें हम कैसे जायेंगे, कैसे घूमेंगे, अैसा हमें लगता हो और जिसको 'छोटा काट'—अंग्रेजीमें 'शॉर्ट कट'—कहते हैं वह हम चाहते हों, यानी यह चाहते हों कि कानून बने, फलाना बने, तो यह बनाना और वैसी अिच्छा रखना हमारा काम नहीं है। कानून बने, जरूर बने, जल्द बने और अच्छा बने; पर अुस काममें हम लगेंगे तो परधर्मका आचरण करेंगे, स्वधर्मका नहीं। हमारा स्वधर्म है कि हम गांव-गांव घूमना शुरू करें और विचार पर विश्वास रखें। यह न कहें कि 'अरे, विचार सुनने-सुनानेसे कब काम होगा?' विचारसे ही काम होगा, क्योंकि हमारा काम विचारसे ही हो सकता है। तो यह विचारकी सत्ता, विचार-शासन हमारा अेक औजार है।

कर्तृत्व और सत्ताका विभाजन

और दूसरा औजार है, कर्तृत्व-विभाजन। सारा कर्तृत्व, सारी कर्म-शक्ति अेक केन्द्रमें केन्द्रित नहीं होनी चाहिये, बल्कि गांव-गांवमें कर्म-शक्ति, कर्म-सत्ता निर्माण होनी चाहिये। अिसलिअे

www.vinoba.in

हम चाहते हैं कि हरअेक गांवको यह हक हो कि वहां कौनसी चीज आये और कौनसी चीज न आये, अिसका निर्णय वह खुद कर सके। अगर कोअी गांव चाहता है कि हमारे यहां कोल्हू चले और मिलका तेल न आये, यानी मिलका तेल आनेसे रोकें, तो अुसे रोकनेका हक होना चाहिये। जब हम यह बात करते हैं, तो अधिकारी कहते हैं कि अिस तरह अेक बड़ी स्टेटके अन्दर अेक छोटी स्टेट नहीं चल सकती। तो मैं कहता हूं कि सत्ताका विभाजन अगर हम नहीं करेंगे, कर्तृत्वका विभाजन नहीं करेंगे तो सेना-बल अनिवार्य है, यह समझ लीजिये। तो फिर सेनाके बगैर आज तो चलेगा ही नहीं, और कभी भी नहीं चलेगा। फिर कायमके लिअे यह तय कीजिये कि सेना-बलसे काम लेना है और सेना सुसज्ज रखनी है। फिर यह न बोलिये कि हम सेनासे कभी-न-कभी छुटकारा चाहते हैं। अगर कभी-न-कभी सेनासे छुटकारा चाहते हों, तो जसा परमेश्वरने किया है, वैसा हमको करना चाहिये। परमेश्वरने अक्लका विभाजन कर दिया। हरअेकको अक्ल दे दी — बिच्छूको भी दी, सांपको भी दी, शेरको भी दी, मनुष्यको भी दी। कमबेशी सही, लेकिन हरअेकको अक्ल दे दी और कहा कि अपने जीवनका काम अपनी अक्लके आधारसे करो। और तब सारी दुनिया अितनी अुत्तम चलने लगी कि वह विश्रांति ले सकता है और यहां तक कि लोगोंको शंका भी होती है कि परमेश्वर है या नहीं। हमको राज्य अैसा ही चलाना होगा जिससे शंका आ जाय कि कोअी राज्य-सत्ता है या नहीं। हिन्दुस्तानमें शायद राज्य-सत्ता नहीं है अैसा भी लोग कहें, तब हमारा राज्य-शासन अहिंसक होगा। अिसलिअे हम ग्राम-राज्यका अुद्घोष करते हैं और चाहते हैं कि ग्राममें नियंत्रणकी सत्ता हो। अर्थात् ग्रामवाले नियंत्रणकी सत्ता अपने हाथमें लें। यह भी अेक जनशक्तिका प्रश्न आया कि गांववाले खुद खड़े हो जायं, निर्णय करें कि फलानी चीज हमको पैदा करनी है। और सरकारके पास मांग करें कि फलाना माल यहां नहीं आना चाहिये, अुसको रोकिये। वह अगर नहीं रोकती है, यानी रोक नहीं सकती, रोकना चाहती है तो भी मान लीजिये कि रोक नहीं सकती, तो अुसके विरोधमें खड़े होनेकी हिम्मत करनी होगी। और अुससे अुस सरकारको अत्यन्त मदद पहुंचेगी, क्योंकि अुसीसे सैन्य-बलका छेद होगा। अिसके बगैर सैन्य-बलका कभी छेद नहीं हो सकता। यह बात कभी नहीं हो सकती कि दिल्लीमें कोअी अैसी अक्ल पैदा हो जाय, चाहे वह ब्रह्मदेवकी अक्ल हो, जिसको चार दिमाग हैं और जो चारों दिशाओंमें देख सकता है। कितनी ही बड़ी अक्ल हो, यह हो नहीं सकता कि हरअेक गांवके सारे कारोबारका नियंत्रण और नियोजन वहांसे हो और वह साराका सारा सबके लिअे लाभदायी हो। अिस वास्ते 'नेशनल प्लैनिंग' के बजाय 'विलेज प्लैनिंग' होना चाहिये। 'बजाय' मैंने कह दिया। बेहतर तो यह कहना होगा कि नेशनल प्लैनिंगका ही अर्थ विलेज प्लैनिंग होना चाहिये। और अुस विलेज प्लैनिंगकी मददके लिअे जो कुछ करना पड़ेगा, अुतना दिल्लीमें किया जायगा। तो यह है हमारे कार्यक्रमका अेक दूसरा अंश। अेक तो पहले बताया था विचार-शासन और यह बताया कर्तृत्व-विभाजन। तो हम जो कुछ करते हैं, वह सारा कर्तृत्व-विभाजनकी दिशामें करना चाहते हैं। अिसलिअे हम गांवोंमें जमीनका बंटवारा करना चाहते हैं।

राष्ट्रकी महान संपत्ति हम खो नहीं सकते

जमीनके बारेमें जब कभी सवाल पैदा होता है, तो लोग यही कहते हैं कि 'सीलिंग' बनाओ, अधिक-से-अधिक जमीन कितनी रखी जाय, यह सोचो। जब कि यह भूदान-यज्ञका आन्दोलन जोर पकड़ रहा है और जनतामें अेक भावना पैदा हो रही है, तब यह बात बोली जा रही है। लेकिन मैं कहता हूं कि पहले तो कम-से-कम जमीन हरअेकको कितनी देना है, यह तय करो। यह मैं क्यों कह रहा हूं? अिस वास्ते कह रहा हूं कि मैं कर्तृत्व-विभाजन चाहता हूं। जितने भी मजदूर हैं, वे सारे आज दूसरोंके हाथमें काम करते हैं। काम तो वे करते हैं, लेकिन अुनमें कर्तृत्व नहीं है। गाड़ी भी चलती है, लेकिन गाड़ीको हम कर्ता नहीं कहते, क्योंकि वह चेतनविहीन है। तो ये जो मजदूर खेतोंमें काम करते हैं, वे चेतनविहीन जैसा काम करते हैं। हाथोंसे काम करते हैं, पावोंसे काम करते हैं। लेकिन अुनके दिमागसे, अुनके दिलसे यह काम हो, अैसा हम चाहते हैं। लोग कहते हैं कि हिन्दुस्तानके मजदूरोंमें अुतनी अक्ल नहीं है अिसलिअे अुनका दूसरोंके हाथमें रहना ही बेहतर है। तो मैं कहता हूं कि यह अहिंसाका तरीका नहीं है। अुनमें जो अक्ल है अुसका परित्याग कर दें, तो दूसरी कोअी अक्ल, दूसरा कोअी खजाना हमारे पास नहीं है।

माना कि अेक मजदूरकी अक्लसे किसी पूंजीवाले भाअीकी अक्ल ज्यादा है। लेकिन कुल मिलाकर देशमें मजदूरोंकी जो अक्ल है, अुस अक्लकी बराबरी दूसरी कोअी अक्ल नहीं कर सकती और अुस अक्लका अगर हमको अुपयोग न मिले तो हमारा देश बहुत खो देता है। अिस वास्ते जरूरी है कि मजदूरोंकी अक्लका, जैसी भी वह आज है, पूरा अुपयोग हो। अिसके साथ-साथ अुनकी अक्ल बढ़े, अैसी भी योजना चाहिये और अुनकी अक्ल बढ़ानेकी जो भी योजना करेंगे, अुसमें यह भी अेक योजना होगी कि अुनको जमीन दी जाय। अलावा अिसके कि हम अुनको और तालीम दें, अुनके हाथमें जमीन देना भी अेक तालीमका ही अंग होगा और अुनकी अक्ल बढ़ानेका भी वह अेक साधन होगा।

तो यह है कर्तृत्व-विभाजन और अुस दिशामें हम जो सोचते हैं। हमारे कार्यक्रमके जो दो पहलू हैं, वह मैंने बताये और अुन पहलुओंके मूलमें जो भूमिका है, वह भी बतायी। तो कार्य-पद्धतिके बारेमें कुछ कहा और अुसके बाद कार्य-विभाजन किस तरह करना चाहिये, कार्यक्रम क्या होना चाहिये, अुसके बारेमें भी थोड़ासा कहा। अब हम कार्य-रचना पर आते हैं। अुसके बारेमें भी थोड़ेसे विचार बता दूं।

(अपूर्ण)

स्मरण-यात्रा

[बचपनके कुछ संस्मरण]

काका कालेलकर

कीमत ३–८–० डाकखर्च १–०–०

शराबबन्दी क्यों?

भारतन् कुमारप्पा

कीमत ०–१०–० डाकखर्च ०–५–०

लोक-जीवन

काका कालेलकर

यह मराठी पुस्तक 'हिंडलग्याचा प्रसाद' नामक पहले छपी हुअी पुस्तकका संक्षिप्त संस्करण है। अिसमें लेखकने धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक वगैरा अनेक आधुनिक प्रश्नोंकी सर्वथा नअी दृष्टिसे चर्चा की है।

कीमत १–४–० डाकखर्च ०–६–०

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद – ९

www.vinoba.in

हरिजनसेवक

९ मअी १९५३

आंध्र और शराबबन्दी

'आंध्रका नया राज्य' शीर्षक लेखमें (देखिये 'हरिजनसेवक', १८-४-'५३) मैंने यह सुझाव पेश किया था कि मद्रास राज्यसे अलग हो जाने पर भी आंध्रको शराबबन्दीकी नीति नहीं छोड़ना चाहिये और कहा था कि न्यायमूर्ति वांचूको अपनी रिपोर्टमें यह सवाल छेड़ना ही नहीं चाहिये था। मद्रासके 'अिण्डियन रिपब्लिक' पत्रने अपने २२ अप्रैल, १९५३ के अंकमें अपने सम्पादकीयमें मेरी अिस सूचना पर आक्षेप किया है। मुझे अभी भी अैसा ही लगता है कि अगर न्यायमूर्ति वांचूने अपनी रिपोर्टमें अिस नये राज्यकी आयका सवाल जिस तरह अुठाया है, अुसी तरह अुठाना था, तो अुनकी समझमें यह आना चाहिये था कि शराबबन्दीकी हमारी राष्ट्रीय नीति अर्थ, कानून और राज्यकी रुपया-पैसा-सम्बन्धी सभी दृष्टियोंसे बुद्धिमत्तापूर्ण है। और मैं मानता हूं कि जहां तक शराबबन्दीकी नीतिका सवाल है, कम-से-कम वहां तक तो आंध्रको अपने जनक-राज्यकी ही नीति पर आरूढ़ रहना चाहिये। शराबबन्दीके सम्बन्धमें हमारे संविधानका राष्ट्रीय आदेश आखिर अुसके लिअे भी है, और अुसे तो अपना सौभाग्य मानना चाहिये कि मद्य और मादक द्रव्योंकी बन्दीकी कोशिश अुसे नये सिरेसे नहीं करना पड़ रही है, की हुअी मिली है, तथा वह अिस सुयोगका लाभ अिस कोशिशको सही दिशामें और आगे बढ़ानेमें कर सकता है।

अुक्त अखबारने अिस नीतिकी बुद्धिमत्ताके विषयमें भी आक्षप अुठाया है, आश्चर्यकी बात तो यह है कि यह आक्षेप, जिसे यह पत्र 'शराबबन्दीका नैतिक पहलू' कहता है, अुसके आधार पर अुठाया गया है। अुसके अनुसार यह नैतिक पहलू अिस प्रकार है:

> "पहली बात तो यह है कि अिस नीतिकी अनिवार्यताका मन पर हानिकर प्रभाव होता है। (किसके मन पर? —सं०) किसी भी तरहकी अनिवार्यताके खिलाफ लोगोंके मनमें जो स्वाभाविक नफरत होती है — वह और लोगोंके बरतावमें अुससे पैदा होनेवाली लुकाव-छिपावकी आदत जनताके नैतिक सामर्थ्यका नाश करती है।"

अिस अखबारके अनुसार शराबबन्दीका सिर्फ नैतिक ही नहीं, बौद्धिक पहलू भी है। अुसका वर्णन अिन शब्दोंमें किया गया है:

> "भारतमें अधिकांश जनता अपढ़ और अज्ञान है। अुसका बौद्धिक स्तर बहुत नीचा है। (क्या सचमुच अैसा है? यह अखबार जिस तरह बहस करता है, अुस तरह बहस करनेकी पंडिताअी चाहे अुनमें न हो, लेकिन अिसे तो ज्ञानवान होना नहीं कहते। —सं०) शराबबन्दीके मूलमें जो नैतिक या सामाजिक सिद्धान्त हैं, अुन्हें समझना कठिन है। अिसलिअे जरूरत लोगोंकी बौद्धिक समझका स्तर अूपर अुठानेकी है।"

अिसी तरह आगे यह अखबार शराबबन्दीकी आरोग्य-सम्बन्धी बाजूकी बात भी करता है:

> "दूसरी जरूरत लोगोंका आरोग्य सुधारनेकी है। यह तो सब लोग स्वीकार करेंगे ही कि हमारी जनताके स्वास्थ्यका स्तर बहुत नीचा है। अगर अिन सारी चीजोंमें ठीक सुधार हो जाय, तो लोग खुद शराबकी बुराअी समझ लेंगे और अुससे दूर रहेंगे।"

अैसी दिखाअू दलीलोंके आधार पर अन्तमें अखबार अपने कथनका अुपसंहार करते हुअे कहता है:

> "राज्यको अपनी सारी साधन-सामग्री अिकट्ठी करना चाहिये। (क्या शराबका नशा और अिस अभिशापका जो फल आता है, वह राज्यके लिअे साधन-सामग्री-रूप होता है? —सं०) अुसे आर्थिक दृष्टिसे सशक्त बनना चाहिये और शिक्षा, डॉक्टरी मदद, रहनेके लिअे घर आदिकी व्यवस्था करके लोगोंका जीवन-मान अूपर अुठाकर ही सामान्य क्रममें शराबकी बुराअी रोकनेका प्रयत्न करना चाहिये। शिक्षासे बौद्धिक शक्ति बढ़ेगी और अुसके द्वारा ही यह सुधार सिद्ध होगा।"

सार्वजनिक धन खर्च करके लोगोंको शराब और दूसरे मादक द्रव्य देकर और अिस तरह अुनकी नैतिक, बौद्धिक और आर्थिक बरबादी करके अुनकी दशा सुधारने और अुनकी समझका स्तर अूंचा अुठानेका यह बढ़िया अुपाय है! शिक्षासे जिस बौद्धिक शक्तिके बढ़नेकी अपेक्षा है, वह क्या यही है? असली बात यह है कि हमारी मौजूदा समाज-व्यवस्थामें शिक्षा, आरोग्य तथा समाज-कल्याणके अैसे ही अन्य कामोंके नाम पर आज जो कुछ चल रहा है, अुससे लाभ अुठानेवाले मध्यम और अूपरके वर्गके लोग यह चाहते हैं कि अिन कामोंके लिअे पैसा शराब-गांजा-अफीम आदिकी दुकानोंके जरिये गरीबोंको ठगकर अुनकी गाढ़ी कमाअीमें से ही खींचा जाय। सच पूछो तो यह चोरी ही है, और अिस तरह चोरीसे पाया हुआ यह पैसा अूपरके वर्गोंके हितमें खर्च होता है। रिश्वतखोरी और गैरकानूनी शराब आदिका काल्पनिक डर तो अिन वर्गोंके ही दिमागकी अुपज है, और अुसमें अुनका मतलब मनके पापको छिपाकर सज्जनताका स्वांग रचना है। अन्यथा आम जनताको अिसका सहज बोध और अनुभव है कि शराबबन्दी अुन्हें गांधीजीका दिया हुआ बड़ा वरदान है। तो हम समय रहते सावधान हो जायं, नहीं तो वह दिन आ रहा है जब गरीब जनता बहुत नाराजीके साथ यह समझेगी कि अुपरले वर्गके बुद्धिवादी शराबबन्दीका विरोध अिसलिअे करते हैं कि अुन्हें गरीबोंसे अपने लाभके लिअे पैसा मिलता रहे। यदि भारतमें राज्य अुन्नतिकी ओर बढ़ना चाहता है, और अुसे बढ़ना चाहिये, तथा यदि वह गरीबों और दलितोंका हित करना चाहता है, तो अुसे अैसी मिथ्या दलीलोंके फेरमें नहीं पड़ना चाहिये जैसी कि अिस अखबारने की है। हमें यह समझ लेना चाहिये कि 'शराबकी आय', यह अेक निरर्थक और भुलावेमें डालनेवाला शब्दप्रयोग है। जैसा कि आन्तरराष्ट्रीय मद्य-निषेधक संघके दक्षिणी अेशिया विभागके अध्यक्ष मि० रॉबर्ट पियर्सनने ऑल अिंडिया रेडियोके बम्बअी स्टेशनसे बोलते हुअे कहा था, "शराबके व्यापारके कारण राज्यको जो पैसा खर्च करना पड़ता है और समाजकी जो बरबादी होती है, अुसकी तुलनामें शराबसे होनेवाली आय नगण्य-सी है। . . . शराबसे होनेवाली आमदनीका लाभ निरा भ्रम है; वह रेगिस्तानके मुसाफिरोंका मजाक अुड़ानेवाले और अुन्हें धोखा देनेवाले किसी मृगजलसे भी ज्यादा भयंकर है।" अुनका यह भाषण अिसी अंकमें अन्यत्र दिया जा रहा है, अिसलिअे मैं अुसमें से और अधिक अुद्धरण यहां नहीं देना चाहता। हम बुद्धिवादी कहलानेवालोंको यह समझ लेना चाहिये कि हम लोग, जिनकी आज हमारे राज्यमें प्रबलता है, भारतकी गरीब जनताकी दिलसे चिन्ता करते हैं और अुसीके

www.vinoba.in

कल्याणका प्रयत्न करते हैं, —अिस बातकी अेक बड़ी कसौटी शराबबन्दी है। यदि हम शराबबन्दीके पक्षमें हैं, तो ही हमारा दावा प्रामाणिक है, अन्यथा नहीं।

२९-४-'५३ **मगनभाअी देसाअी**

(अंग्रेजीसे)

शराबकी आमदनी मृगजल जैसी है

[आन्तरराष्ट्रीय मद्यनिषेधक संघके दक्षिणी अेशिया विभागके अध्यक्ष श्री रॉबर्ट पियर्सनने २६ अप्रैल, १९५३, रविवारके दिन ऑल अिन्डिया रेडियोके बम्बअी स्टेशनसे "शराबकी आमदनीका क्या होगा?" विषय पर जो भाषण किया अुसमें से नीचेका भाग यहां दिया जाता है।]

पिछले तीन महीनोंमें मैंने भारतके अधिकतर भागोंका दौरा किया है। अिस यात्रामें मुझे कअी बड़े दिलचस्प लोगोंसे मिलनेका सौभाग्य मिला। स्वभावतः मादक द्रव्य निषेधके महान अुद्देश्यके विषयमें अुनकी प्रतिक्रिया और खास तौर पर शराबबंदीके विषयमें अुनका रुख जाननेमें मेरी दिलचस्पी रही है। मेरी जिज्ञासाने हरअेक स्तरके स्त्री-पुरुषोंसे मेरा सम्पर्क स्थापित कराया। मैंने कॉलेजके प्रोफेसरोंसे बात की, व्यापारी और व्यवसायी लोगोंसे बात की, सफेदपोश बाबुओंसे बात की और मेहनतकश किसानोंसे भी बात की। दक्षिण भारतके हरेभरे धानसे लहलहाते हुअे खेतोंसे लेकर आपके अनुपम हिमालयकी हिममंडित चोटियों तक मैंने शराबबंदीके बारेमें लोगोंमें अेक ही मुख्य प्रश्न बार-बार अुठता पाया है: 'शराबबंदीको अपनानेसे हमें आमदनीका जो नुकसान हो रहा है या होगा, अुसे हम कैसे पूरा करेंगे?'

मैं देखता हूं कि आज भारतके हर हैसियतके लोगोंके दिमागमें शराबबंदी और आमदनीके नुकसानका प्रश्न बहुत गहराअीसे जुड़ा हुआ है। शराबबंदीके प्रश्नके साथ आमदनीके नुकसानका प्रश्न अुठे बिना नहीं रहता। अुदाहरणके लिअे, मैं शराबबंदीवाले अेक भागमें कुछ खरीदी कर रहा था। जब क्लार्कने मेरे हाथमें बिल दिया, तो अुसने मेरा ध्यान कीमतमें शामिल किये गये टैक्सकी तरफ खींचते हुअे कहा: "अगर हम शराबबंदीके कारण अितना पैसा न गंवाते, तो हमें खरीद-कीमतके साथ ये सब टैक्स नहीं जोड़ने पड़ते।"

अेक दूसरे मौके पर, अभी हालमें, मैं अेक सुशिक्षित सज्जनके साथ, जिन्होंने अेक लेखक और अेक बड़ी युनिवर्सिटीके भूतपूर्व प्रोफेसरके रूपमें अपना परिचय मुझे दिया, रेलयात्रा कर रहा था। हमारी बातचीत जल्दी ही शराब वगैरा नशीले पेयों और शराबबंदीके प्रश्नकी ओर मुड़ी। अुन्होंने कहा: "भारत जैसे देशके लिअे शराबबंदी बहुत ज्यादा महंगा प्रयोग है। हम अेक स्वतंत्र राष्ट्रके नाते दुनियामें अपना स्थान प्राप्त करनेके प्रयत्नमें लगे हुअे हैं। हमारे सामने अपने लोगोंकी हालतको सुधारनेके कअी जरूरी काम पड़े हैं। हमें बड़ी-बड़ी सिंचाअीकी योजनाओंका विकास करनेकी जरूरत है, ताकि हम जमीनको ज्यादा अुपजाअू बनाकर ज्यादा अन्न पैदा कर सकें। हमें अपने अुद्योगोंका विकास करना है। हमें अपने यातायात और डाक-तारकी सुविधायें बढ़ानी और विकसित करनी हैं। हमें आजसे ज्यादा स्कूलों और अस्पतालोंकी जरूरत है। लेकिन अिन सब योजनाओं और कामोंके लिअे पैसेकी जरूरत है। जिन राज्योंमें शराबबंदी है, वे शरावसे होनेवाली करोड़ों रुपयोंकी आमदनी हर साल गंवाते हैं। हम अितनी भारी रकमकी हानि नहीं अुठा सकते, जिसकी हमें अपने राष्ट्रीय विकासके लिअे बड़ी जरूरत है।"

बार-बार मैंने लोगोंके मुंहसे यही दलील सुनी है। आमदनीका नुकसान आज भारतमें शराबबंदीके खिलाफ अेक सबसे बड़ा अेतराज है। लेकिन अब हम हकीकतों पर विचार करें। जायज शराबके कारण किसी राष्ट्रके नागरिकोंको जो नुकसान लाजिमी तौर पर होता है, अुसके बनिस्बत शराबकी आमद छोड़नेके कारण क्या अुसे ज्यादा नुकसान होता है? दूसरे शब्दोंमें, क्या शराबबंदीसे होनेवाली आमदनीकी हानि अुस बढ़े हुअे खर्चसे ज्यादा है, जो किसी राज्यको शराबके कारण बढ़नेवाले गुनाहोंको रोकनेमें और जनकल्याणकी बढ़ी हुअी मांगें पूरी करनेमें अनिवार्य रूपसे करना होगा?

जायज शराब नशाखोरीको बढ़ाती है। और नशाखोरीका मतलब है ज्यादा गुनाह, ज्यादा दुर्घटनायें, ज्यादा घरोंका टूटना, ज्यादा कंगाली और नौजवानोंमें बढ़ा हुआ दुराचार। राज्य अिन समस्याओंकी अुपेक्षा नहीं कर सकता। बढ़े हुअे गुनाहोंका अर्थ है कानूनके अमल और जेलोंकी व्यवस्थाके लिअे ज्यादा खर्च। ज्यादा दुर्घटनाओंका अर्थ है अस्पतालोंकी ज्यादा सुविधायें खड़ी करना। ज्यादा टूटे घरों, नौजवानोंमें बढ़े हुअे पापाचार और ज्यादा कंगालीकी समस्याओंसे निबटनेके लिअे राज्यको ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। अिसे आप कभी न भूलें कि जायज शराबके पीछे ये मांगें तो अनिवार्य रूपसे आयेंगी ही; और दूसरे राष्ट्रोंका अनुभव यह बताता है कि सरकारको जायज शराबके कारण जो खर्च करना पड़ता है, वह शराबसे होनेवाली आमदनीसे कहीं ज्यादा होता है।

* * *

लेकिन शराबके व्यापारके सरकारी आंकड़ों पर अेक नजर डाली जाय, तो मालूम होगा कि तथाकथित आमदनीके आंकड़े कैसे पूर्णतया अधूरे और धोखा देनेवाले हैं। . . .

यह अेक बुनियादी सचाअी है, जिसे हमें भूलना नहीं चाहिये: **शराबके व्यापारसे जो सामाजिक बरबादी होती है और अुसके कारण सरकारको जो खर्च करना पड़ता है, अुसकी तुलनामें शराबसे होनेवाली आमदनी बिल्कुल नगण्य है।**

अुदाहरणके लिअे, मेरे अपने देश अमेरिकाको ही लीजिये। शराबका व्यापार केवल पैसेके रूपमें ही अमरीकी जनता पर **प्रतिदिन** लगभग ३३,०००,००० डालरका या **प्रतिघंटे** १४,००,००० डालरका खर्च डालता है! अिन आंकड़ोंको आप ५ से गुणा कर दें, तो आपको रुपयोंके रूपमें अिस भारी खर्चका खयाल आ जायगा। अिसका विचार कीजिये। शराबके व्यापारके लिअे अमरीकी जनताको प्रतिदिन १६५ करोड़ रुपये या प्रतिघंटे ७० लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं। और हमारा देश नौजवानोंको शराबसे बचाने या प्रौढ़ोंको अुससे बचनेकी चेतावनी देना तो दूर रहा, हर साल शराबके व्यापारसे ३ अरब डालर पैदा करता जाता है और अुसे कानूनन् अुन लोगोंकी जेबसे, जिन्हें वह अखबारों, रेडियो और अभी हालके बरसोंमें टेलिविज़न द्वारा शराब खरीदनेकी लुभावनी व भड़कीली अपील करके ठगता है, प्रतिवर्ष ९ या १० अरब डालर हथियानेकी अिजाजत देता है।

मेस्सेच्युसेट्स राज्यकी धारासभाके सामने जो रिपोर्ट पेश की गअी है, अुसमें अेक प्रसिद्ध जजकी अध्यक्षतामें जांच करनेवाली कमेटीने बताया है कि अुनके राज्यको शराब पर कुल ६०,०००,००० (३० करोड़ रुपये) डालरका सीधा खर्च करना पड़ता है, जब कि शराबके अुद्योग पर लगाये गये करोंसे लगभग १३,०००,००० (६ करोड़ ५० लाख रुपये) डालरकी आमदनी होती है। अिस कमेटीने आगे बताया कि अगर शराबके व्यापारके अप्रत्यक्ष

www.vinoba.in

परिणामोंका खयाल करें, तो राज्यका नुकसान भयंकर रूपमें बढ़ जायगा। अिस बातका सबूत है कि आम तौर पर शराब-अुद्योग पर लगाये गये करोंसे राज्यको जो आमद होती है, अुससे लगभग ६ या ८ गुना खर्च अुसे शराबके कारण करना पड़ता है।

अिसी राज्यमें सावधानीसे की गअी जांचोंसे यह पता चला है कि पारिवारिक सम्बन्धोंका फैसला करनेवाली अदालतके सामने जो मामले पेश किये गये, अुनमें से ४२ फीसदीका सीधा कारण शराब थी और ४७ फीसदी मामलोंका कारण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमें माता-पिता या दोनोंके शराबके नशेमें चूर हो जानेसे पैदा हुअी परिस्थितियां थीं। बच्चोंको जीवनकी पूरी सुविधायें न मिलने या अुनके दुराचारी होनेका यही मुख्य कारण है। अिसी समस्याको हल करनेमें राज्यको बड़ी मात्रामें पैसा खर्च करना पड़ता है।

मेस्सेच्युसेट्स राज्यमें यह भी पाया गया कि मृत्यु या कैदकी सजा दिये जाने लायक ५० फीसदी गुनाहोंका तथा ८५ फीसदी दुराचारों या छोटे गुनाहोंका कारण शराबखोरी है। शराब राज्यमें २५ फीसदी मानसिक रोगियोंके लिअे सीधी और कम-से-कम १५ फीसदी और अैसे रोगियोंके लिअे अप्रत्यक्ष रूपसे जिम्मेदार है। अपराधियों और मानसिक रोगियोंकी चिन्ता करनेमें राज्यको अनाप-शनाप पैसा खर्च करना पड़ता है। मेरे मित्रो, आप याद रखें कि जायज शराबके लिअे देशको भारी खर्च करना पड़ता है। शराबसे होनेवाली अेक रुपयेकी आमदनीके पीछे अुसे राज्य द्वारा शराबके कारण किया जानेवाला खर्च पूरा करनेके लिअे ६ या ८ रुपये देने पड़ते हैं।

शराबसे होनेवाली आमदनीका लाभ निरा भ्रम है; वह रेगिस्तानके मुसाफिरोंका मजाक अुड़ानेवाले और अुन्हें धोखा देनेवाले किसी मृगजलसे भी ज्यादा भयंकर है। आप मेरे ही आर्थिक दृष्टिसे अुचित व्यवसायको लें। अुसका अुत्पादन या अुसकी सेवा समाजको सच्चा या प्रत्यक्ष दिखाअी देनेवाला लाभ पहुंचाती है, जो अुसे टिकाये रखता है। अुसकी वजहसे लोगोंको जो खाद्य-पदार्थ, कपड़ा, मकान आदि बनानेका सामान मिलता है, वह समाजको होनेवाला स्थायी लाभ है। ये चीजें समाजकी सम्पत्तिमें वृद्धि करती हैं और अुसके कल्याणको बढ़ाती हैं। अिन अुद्योगोंमें काम करनेवाले लाखों-करोड़ों लोगोंको जो रोजी या वेतन मिलता है, वह अिन चीजोंसे जनकल्याणमें पहुंचनेवाली सहायताका अेक भाग ही है। यहां तक कि अुसका विज्ञापन भी जानकारी बढ़ानेवाला, बुद्धिको बढ़ानेवाला और रचनात्मक या सर्जक होता है।

लेकिन शराबका व्यापार अैसा नहीं है। अिस सम्बन्धमें हम काफी हद तक फैले हुअे अिस विचारको हमेशाके लिअे छोड़ दें कि शराबके व्यापारसे या अुसके जरिये मिलनेवाले पैसेका आर्थिक दृष्टिसे वही मूल्य है, जो सम्पत्ति पैदा करनेवाले किसी अुचित अुद्योग पर खर्च किये गये पैसेसे होनेवाली आमदनीका है।

शराब मजदूरोंको जो पैसा या मजदूरी देती है, वह पानेवाले मजदूरोंका पोषण भले करे, लेकिन अुससे जनताका कोअी कल्याण नहीं होता। अुल्टे वह मजदूरी जनता पर पड़नेवाला अेक बोझ और जनताके पैसेकी बरबादी है, जिसकी तुलनामें अुसे कोअी लाभ नहीं होता। अगर हम शराबके नतीजों और बुराअियोंकी अुपेक्षा करके पैसा पैदा करनेके लिअे शराबके व्यापारको जायज मानें, तब तो हम आजकी दूसरी कअी बुराअियोंको भी जायज करार देकर आमदनी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोअी यह सुझाये कि राष्ट्रीय आय बढ़ानेके लिअे चोरी और गबनको कानूनी घोषित करना चाहिये, तो यह कितना हास्यास्पद मालूम होगा! बेशक, ये दोनों सम्पत्तिके अधिकार पर हमला करते हैं, फिर भी वे अपने शिकारोंका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पतन नहीं करते। लेकिन शराबका व्यापार आम तौर पर अैसा ही करता है।

हम आगे बढ़कर यह भी दिखा सकते हैं कि जिन मजदूरोंको शराब काम देती है, वे अुचित और कल्याणकारी अुत्पादनके क्षेत्रसे हटा लिये जाते हैं; और अुस हद तक शराब स्वास्थ्यकारी चीजोंके बाजारको घटाती है, जिन्हें बनानेके लिअे ज्यादा मजदूरोंकी जरूरत होती।

हमने अूपरसे दिखाअी देनेवाले शराबके जो बुरे परिणाम गिनाये हैं, अुनसे कहीं ज्यादा नुकसान राष्ट्रको शराबके कारण होता है। अमेरिकाकी जांचोंसे मालूम होता है कि कारखानोंमें काम करनेवाले जो मजदूर काम छोड़कर अिधर-अुधर भटकते और समय बरबाद करते हैं, अुनमें से कम-से-कम ११ फी सदीकी गैरहाजिरीका मुख्य कारण शराब होती है। अन्दाज लगाया गया है कि अिससे हर साल अुद्योगोंको लगभग १ अरब डालरका नुकसान होता है। अेक जांचमें अिस बातके आंकड़े दिये गये हैं कि कितने मजदूर काम छोड़कर अिधर-अुधर भटके, अिसमें अुन्होंने कितना समय बरबाद किया और शराब पीनेके कारण अुन्हें कितनी मजदूरी खोनी पड़ी। अिस जांचसे यह अन्दाज लगाया गया था कि शराब पीनेवाले मजदूर अिस तरह जो समय बिगाड़ते हैं और अच्छा काम नहीं करते, अुसके कारण अमेरिकाको हर साल लगभग १ अरब डालर खोने पड़ते हैं। शराब पीनेवाले मजदूर और दिनोंमें होनेवाली औसतन् दो दुर्घटनाओंके बजाय सोमवारको दुगुनी या तिगुनी दुर्घटनाओंके शिकार होते हैं। सोमवार अैसा दिन है, जब मेरे देशमें पियक्कड़ मजदूरों पर नशेकी थोड़ी-बहुत खुमारी बनी रहती है। अिसलिअे वे आवश्यक सावधानीसे काम नहीं करते और दुर्घटनाओंके शिकार होते हैं।

शराबके नशेमें मजदूर काम छोड़कर अिधर-अुधर भटकते रहते हैं और अच्छा काम नहीं करते अिससे राष्ट्रको बहुत बड़ा नुकसान होता है।

कौन कहता है कि शराबबन्दीसे आमदनीका नुकसान होगा? राज्यको जायज शराबसे जो आय होती है, अुससे कअी गुना ज्यादा अुस पर अुसे खर्च करना पड़ता है। शराबके व्यापारके कारण राज्यको जो पैसा खर्च करना पड़ता है और समाजकी जो बरबादी होती है, अुसकी तुलनामें शराबसे होनेवाली आय नगण्य-सी है। शराबसे होनेवाली तथाकथित आय सिंचाअी-योजनाओं और ज्यादा अच्छे स्कूल खोलनेमें खर्च होनेके बजाय अुस कअी गुना बढ़े हुअे खर्चमें लगेगी, जो गुनाहोंको रोकने और कानूनके अमलमें, मानसिक रोगियोंके दवाखाने चलानेमें और नौजवानोंमें बढ़नेवाले दुराचार और गरीबीकी समस्यायें हल करनेमें होगा। और ये सारी समस्यायें जायज शराबके अनिवार्य परिणाम हैं।

अेक बातको आप कभी न भूलें: अनुभवसे पता चलता है कि शराबसे आमदनी होती है यह कहना निरा धोखा है। जायज शराबके कारण सरकारों और व्यक्तियोंको काफी बड़े खर्चमें अुतरना पड़ता है।

(अंग्रेजीसे)

www.vinoba.in

कार्यसिद्धिके लिअे अगला कदम

दो वर्षमें पच्चास लाख अेकड़ जमीन भूदान-यज्ञमें प्राप्त करनेका जो महान संकल्प अप्रैल १९५२ में सेवापुरीमें हमने किया था, अुसे चांडिलमें फिरसे दोहराया ही नहीं, बल्कि प्रतिज्ञा भी की कि आगामी अेक सालमें पच्चीस लाख अेकड़ जमीन प्राप्त करने मात्रसे हम अपनी कार्यसिद्धि न मानकर १९५७ के पहले पांच करोड़ अेकड़ जमीन दानमें प्राप्त कर समताधिष्ठित तथा शोषणहीन सर्वोदय-समाजके निर्माणके लिअे आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार करेंगे।

गिरिराज हिमाचलकी अेक चोटी पर चढ़ जानेके बाद अुससे भी अूंची दूसरी चोटीके दर्शनका आनंद पर्वतारोहीको प्राप्त होता है और अुससे अुसका अुत्साह और हौसला अधिक बढ़ जाता है। अप्रैल १९५१ में विनोबाजीको सौ अेकड़का पहला दान मिला। सेवापुरीके संमेलन तक लोगोंने अुन्हें अेक लाख अेकड़ जमीन दान दी थी। सेवापुरीमें सर्वोदय कार्यकर्ताओंने दो वर्षमें पच्चीस लाख अेकड़ जमीन भूदान-यज्ञमें प्राप्त करनेका संकल्प किया।

भूदान-यज्ञ ही प्रधान कार्य

चांडिल सम्मेलन तक अिस पच्चीस लाखमें से ७-८ लाख अेकड़ जमीन मिली। अुत्तर प्रदेशने चार लाख ७५ हजार अेकड़ जमीन दानमें प्राप्त कर अपना पांच लाखका संकल्प लगभग पूरा कर दिया। अिस कार्यके लिअे लोगोंमें और कार्यकर्ताओंमें दृढ़ श्रद्धा और अचूक दृष्टि निर्माण करनेमें तथा संकल्प पूरा करनेके लिअे आवश्यक संगठन खड़ा करनेमें सेवापुरीके बाद कुछ समय गया। फिर भी अेक वर्षमें छोटे-बड़े हजारों जमीन-मालिकोंने ७-८ लाख अेकड़ जमीन भूदान-यज्ञमें दी, अिससे सिद्ध होता है कि भूदान-यज्ञकी अग्नि जनताके मनमें प्रज्वलित हुअी है और वह अेक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया है। अुसमें जोश और गति लानेके लिअे जीवन-निष्ठ कार्यकर्ता ज्यादा-से-ज्यादा तादादमें आगे आयें, यह जरूरी है। अिसलिअे चांडिलके प्रस्ताव द्वारा सर्वोदय-विचारमें श्रद्धा रखनेवाले लोगों और खासकर रचनात्मक कार्यकर्ताओंको आवाहन किया गया है कि वे भूदान-यज्ञके कामको पहला स्थान दें।

प्रत्यक्ष कामसे प्रचार हो

गत दो वर्षसे देशमें भूदान-यज्ञका लगातार प्रचार चल रहा है। प्रचार जितना भी किया जाय कम ही होता है, अैसा हमेशाका अनुभव है। फिर भी प्रचारमें अैसी अेक अवस्था या समय आता है कि जब प्रत्यक्ष कामसे ही वह अधिक प्रभावशाली बनता है। अिसलिअे अब कार्यकर्ताओंको प्रत्यक्ष भूमिदान प्राप्त करनेमें ही अपनी शक्ति और समय देना चाहिये। यह ध्यानमें रखें कि शरीरकी तत्परता, मनकी अेकाग्रता और चित्तकी निर्वेदताके त्रिवेणी संगम पर ही महान् संकल्प-सिद्धकी पवित्रता तथा सार्थकताका लाभ हो सकता है।

सबका सहयोग लें

आज खेतमें जो फसल खड़ी है, वह सबकी सब अिस वर्ष कट जानी चाहिये। चांडिलके प्रस्ताव द्वारा सर्वोदय-विचारमें श्रद्धा रखनेवाले रचनात्मक कार्यकर्ताओंको तथा नवयुवकोंको संकल्प-सिद्धिके काममें खुदको खपा देनेके लिअे खास आवाहन किया गया है। लेकिन हमें अहिंसा और हृदय-परिवर्तन द्वारा काम करना है, अिसलिअे अिसमें सब लोगोंका समावेश कर लेनेकी नीति हमें रखनी चाहिये।

निश्चित कार्यक्षेत्रके हर गांवसे पांच अेकड़

भूदान-यज्ञमें आहुति देनेवालोंकी संख्या हजारों तक पहुंच चुकी है और वह बढ़ती रहेगी। ये सब छोटे-बड़े दाता हमारे क्रियाशील कार्यकर्ता ही हैं। प्रादेशिक भूदान-यज्ञ-समितिके संचालकोंको चाहिये कि वे जिसकी जैसी शक्ति हो, वैसा अुसे अपने क्षेत्रमें काम देनेकी योजना बनावें। कार्यकर्ताका कार्यक्षेत्र निश्चित किया जाय। अिस निश्चित किये गये क्षेत्रके प्रत्येक गांवमें जाकर सर्वोदयका संदेश बताने और सेवापुरीके प्रस्तावमें कहा है, अुसके अनुसार हर गांवसे कम-से-कम पांच अेकड़ जमीन प्राप्त करनेका संकल्प प्रत्येक कार्यकर्ताको अपने मनमें करना है। अिस निश्चयसे कार्यकर्ता काम करेंगे, तो अप्रैल १९५४ के पहले पच्चीस लाख अेकड़ जमीन प्राप्त करनेका हमारा संकल्प पूरा होगा, अैसी श्रद्धा हम रख सकते हैं।

शंकरराव देव

सरकारी विज्ञापन

ता० २८-४-'५३ के 'टाअिम्स ऑफ अिंडिया' के अग्रलेखमें 'प्रेसके विशेषाधिकारों' के प्रश्न पर कुछ बातें कही गअी हैं, जिनकी ओर अेक पाठक-मित्रने मेरा ध्यान खींचा है। अुनमें से अेक अुस मुद्देको छूती है, जिसका जिक्र मैंने २५ अप्रैलके 'हरिजन' में छपे अपने 'दो सवाल' नामक लेखमें किया है। अुसमें मैंने सुझाया है कि जिस तरह विज्ञापन देनेवाले व्यक्तिको यह तय करनेका अधिकार होता है कि वह कौनसे अखबारको अपना विज्ञापन दे, अुसी तरह सरकारको भी अेक लोकतांत्रिक संस्था होनेके बावजूद यह तय करनेका अधिकार है कि वह कौनसे अखबारको अपने विज्ञापन दे। और अेक शर्तके रूपमें मैंने अुसमें जोड़ा है:

> "प्रजाहितके ट्रस्टीके नाते सरकारको अपना यह अधिकार समाजकी सुरक्षितता और अुसकी नीति, विवेक या सुरुचिकी सर्वसाधारण जरूरतको देखकर आम लोगोंकी भलाअीके लिअे बरतना चाहिये। सरकारके और कामोंकी तरह अुसमें भी किसी तरहका अन्याय नहीं होना चाहिये। अिसलिअे सरकारी विज्ञापन पाना अखबारोंका अबाधित अधिकार नहीं माना जा सकता। यदि अखबार विनय, विवेक तथा सुरुचिका स्तर कायम न रखकर गिरने लगें या राज्य और प्रजाकी सुरक्षितताके लिअे खतरा पैदा करने लगें, तो अुनके प्रति जैसे प्रजा अपनी नापसंदगी जाहिर कर सकती है, अुसी तरह सरकार भी कर सकती है; और जहां आवश्यकता हो वहां वह कानूनसे भी काम ले सकती है। अिसका अर्थ यह कि सरकार कड़वी-मीठी टीकाकी तरफ ध्यान न दे। जैसा कि शुरूमें कहा गया है, प्रामाणिक टीकाकी छूट तो रहनी ही चाहिये। लेकिन अखबार यदि सर्वसाधारण सुरुचि और सज्जनता आदिका भंग करने लगें, तो यह अुनकी स्वतंत्रता नहीं, स्वच्छन्दता ही मानी जानी चाहिये। अिसके खिलाफ राज्य और प्रजा दोनोंको अपनी नाराजी दिखानी ही चाहिये। अखबारोंकी स्वतंत्रता भी अेक जिम्मेदारी है, और अिस बातका सदा ध्यान रखना समाज और राज्यका फर्ज है कि अुस स्वतंत्रताका कभी दुरुपयोग न हो।"

'टाअिम्स ऑफ अिन्डिया' अूपरकी शर्तकी अुपेक्षा करता है और यह कहकर मेरे सुझावका विरोध करता है कि "विज्ञापन देनेवाली सरकारसे खानगी विज्ञापनदाताकी तुलनाका बिलकुल समर्थन नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनोंके बीच बुनियादी भेद है। खानगी विज्ञापनदाताका सारा पैसा अुसका अपना होता है, जब कि सरकारी विज्ञापनोंके संबंधमें पैसा जनताका होता है।" अूपर बताये गये अपने लेखमें मैं यह भेद बता चुका हूं। लेकिन अुससे कोअी खास फर्क पैदा नहीं होता। खानगी विज्ञापनदाता भी अिस अधिकारका मनचाहा अुपयोग नहीं कर सकता। समाजमें व्यक्तियों या संस्था किसीको भी अैसा अबाधित अधिकार नहीं हो सकता। अिसे

www.vinoba.in

सब कोअी स्वीकार करेंगे कि प्रजाके ट्रस्टीके नाते राज्य और अुसकी सरकारको जनहितकी जिम्मेदारी निभानी चाहिये। बेशक, सरकार सुराज्यके हितोंको नुकसान पहुंचाये बिना अिस जिम्मेदारीको छोड़ नहीं सकती। यह सरकारका विशेषाधिकार नहीं, बल्कि अुसकी जिम्मेदारी है। खानगी विज्ञापनदाताकी भी अैसी ही जिम्मेदारी है, यद्यपि छोटे पैमाने पर। क्योंकि वह अपने पैसेका वैसा निरंकुश मालिक नहीं है, जैसा कि 'टाअिम्स ऑफ अिंडिया' अुसे मानता है। वह भी अपने पैसेका अुपयोग जनताके सामूहिक कल्याणके ट्रस्टीके नाते ही कर सकता है, यद्यपि अुसमें अुसका छोटा लाभ समाया हुआ है। खानगी हितको सार्वजनिक हितमें सहायक होना चाहिये, अुसके खिलाफ नहीं जाना चाहिये। यह प्रतिपादन करना गलत सामाजिक दर्शन या अेक खतरनाक सिद्धान्त होगा कि किसी व्यक्तिका पैसा, जमीन-जायदाद और अुसकी मानसिक शक्तियां भी केवल अुसीकी हैं और अुनका मनचाहा अुपयोग करनेका अुसे हक है। जैसा कि गांधीजीने हमें सिखानेका प्रयत्न किया, समाजमें रहनेवाला मनुष्य समाजका ट्रस्टी है, अुसीके भलेके लिअे अुसका अस्तित्व है; अपनी अुपरोक्त चीजोंकी मददसे वह जो कुछ भी करता है, वह सब समाजके कल्याणके लिअे होना चाहिये। अुसका सारा पैसा-टका, जमीन-जायदाद वगैरा अिस अर्थमें अुसीके नहीं है कि वह समाजको हानि पहुंचानेवाले ढंगसे अुनका अुपयोग कर सकता है। समाजने अुसे अिन चीजोंके स्वामित्वका जो अधिकार दिया है, वह अेक जिम्मेदारी है, अेक ट्रस्ट है। यह सिद्धान्त व्यक्तियों या संस्थाओं सभी पर अेकसा लागू होता है। समाजमें किसीको भी असीम या अबाधित अधिकार नहीं हो सकता। बेशक, जनताका पैसा सरकारके हाथमें कोअी मेहरबानीमें बांटनेकी चीज नहीं है; वह अेक जिम्मेदारी है, और जनताके ट्रस्टीके नाते यह देखना राज्यका फर्ज है कि जनतासे वह जो पैसा अिकट्ठा करता है अुसका अच्छेसे अच्छा अुपयोग हो। यह बात कोअी नहीं कहता कि अुसके अुपयोगमें किसी राजनीतिक पार्टिके प्रति पक्षपातकी नीति बरती जाय।

यह भी याद रखना चाहिये कि अूपर जिस ट्रस्टीशीपके सिद्धान्तकी चर्चा की गअी है, वह प्रेसको भी लागू होता है। अुसे यह समझना चाहिये कि विज्ञापन निकालना अुसके लिअे केवल लाभका ही काम नहीं है; वह अेक जिम्मेदारी है। अिसलिअे आम लोगोंको मदद पहुंचाने, शिक्षा देने और सही रास्ता बतानेकी दृष्टिसे प्रेसको अच्छे और बुरे विज्ञापनके बीच भेद करना चाहिये। यह बड़े दुःखकी बात है कि आज प्रेस विज्ञापनके बारेमें अिस दृष्टिसे विचार नहीं करता। हम आशा करें कि प्रेस कमीशन अिस परेशान करनेवाले प्रश्न पर कुछ प्रकाश डालेगा।

अन्तमें सरकारी विज्ञापनोंके बारेमें अेक बात और जोड़ दूं। आम तौर पर सरकारी विज्ञापन खानगी व्यापारिक या व्यावसायिक विज्ञापनके ढंगके नहीं होते। अुनका रूप लगभग सार्वजनिक घोषणा या सार्वजनिक विज्ञप्तिका होता है। प्रेस भी अैसा ही मान कर अुन्हें सार्वजनिक समाचारके नाते अपने कालमोंमें अनुकूल स्थान दे सकता है और व्यापारिक लाभकी दृष्टि छोड़ सकता है। प्रेसकी यह दृष्टि सरकारी विज्ञापनसे पैसे कमानेके अुस गन्दे खयालको ही पूरी तरह बदल देगी, जो मुझे डर है कि विज्ञापनके सामने सार्वजनिक प्रेसके विशेषाधिकारों और स्वतंत्रताके बारेमें हमारे स्पष्ट विचारको विकृत कर देता है।

२-५-'५३ मगनभाअी देसाअी
(अंग्रेजीसे)

काश्मीरकी राजभाषा

अभी हालमें काश्मीर और जम्मूके मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्लाने यह घोषणा की कि नागरी और अुर्दू दोनों लिपियोंमें लिखी जानेवाली अुर्दू राज्यकी राजभाषा होगी। अुन्होंने कहा कि भारतीय संविधानमें भारतकी प्रादेशिक भाषाओंके विकास और समृद्धिकी व्यवस्था की गअी है और अुर्दू काश्मीरकी प्रादेशिक भाषा है। सारे राज्यके लोग अुसे समझते हैं और वह सदियोंसे राज्यकी राजभाषा रही है। अुन्होंने यह भी कहा कि हिन्दीका भी अुचित विचार किया जाना चाहिये, क्योंकि देवनागरी लिपिमें लिखी जानेवाली हिन्दी भारतीय संघकी राजभाषा होगी। शायद अिसी दृष्टिसे अुन्होंने यह घोषणा की कि राजभाषा अुर्दू सीधीसादी और आसान होगी और वह नागरी लिपिमें भी लिखी जायगी। गांधीजीने बार-बार हमसे यह कहा है कि अगर संस्कृतसे लदी हुअी हिन्दी और अरबी-फारसीसे लदी अुर्दूको अितना सादा और आसान बना दिया जाय कि अुसे अुत्तरके आम लोग समझ सकें, तो भाषासे कोअी सम्बन्ध न रखनेवाले कारणों द्वारा पैदा किया हुआ हिन्दी-अुर्दूके बीचका अवांछनीय और कृत्रिम भेद मिटने लगेगा और हमें अेक आसान भाषा मिल जायगी — भले अुसे हम हिन्दी, अुर्दू या हिन्दुस्तानी किसी भी नामसे पुकारें। काश्मीरका प्रयोग गांधीजीके अिस विधानको प्रमाणित करनेवाला अेक स्वागत योग्य प्रयोग हो सकता है। हर हालतमें यह अच्छी बात है कि काश्मीरमें अुर्दूके लिअे नागरी लिपिका भी अुपयोग होगा। अगर दिल्ली, अुत्तरप्रदेश, बिहार वगैरा भी यह तय कर लें कि नागरी या अुर्दूमें लिखी जानेवाली हिन्दी अिन प्रदेशोंकी राजभाषा होगी, क्योंकि अुर्दू वहांकी अेक प्रादेशिक भाषा है, तो भारतके विधानके आदेशानुसार हमारी राष्ट्रभाषाके विकासमें यह अेक अुम्दा चीज होगी। अिस तरह काम किया जाय तो राष्ट्रीय हिन्दीके निर्माण और विकासके लिअे हिन्दी और अुर्दूकी सारी साहित्यिक और सांस्कृतिक सामग्री अिकट्ठी की जा सकेगी — अैसी राष्ट्रीय हिन्दी, जो अुत्तरके आम लोगोंके लिअे ज्यादा सादी और आसान होगी और राष्ट्रभाषाके नाते भी जिसे लोग आजसे ज्यादा स्वीकार करेंगे।

२६-४-'५३ मगनभाअी देसाअी
(अंग्रेजीसे)

राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी

[दूसरा संस्करण]

लेखक: गांधीजी

अनु० काशिनाथ त्रिवेदी

कीमत १-८-० डाकखर्च ०-८-०

नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद-९

विषय-सूची

		पृष्ठ
हमारा अनोखा मिशन – २	विनोबा	७३
आन्ध्र और शराबबंदी	मगनभाअी देसाअी	७६
शराबकी आमदनी मृगजल जैसी है	रॉबर्ट पियर्सन	७७
कार्यसिद्धिके लिअे अगला कदम	शंकरराव देव	७९
सरकारी विज्ञापन	मगनभाअी देसाअी	७९
काश्मीरकी राजभाषा	मगनभाअी देसाअी	८०

www.vinoba.in